

## भारत में नरिधनता में कमी-SBI

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

### चर्चा में क्यों?

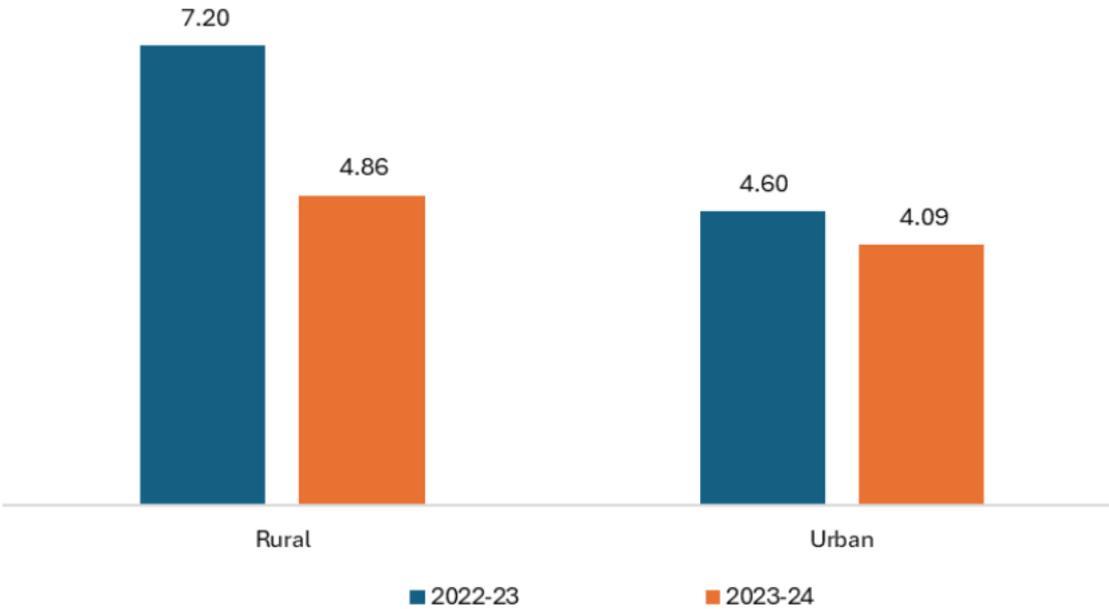
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया शोध रिपोर्ट में ग्रामीण तथा शहरी भारत में गरीबी दर में आने वाली उल्लेखनीय गिरावट पर प्रकाश डाला गया है।

- इस रिपोर्ट में इस गिरावट का श्रेय लक्ष्मि सरकारी हस्तक्षेप, उन्नत ग्रामीण बुनियादी ढाँचे तथा नमिन आय वर्ग के बीच बेहतर उपभोग पैटर्न को दिया गया है।

### SBI रिपोर्ट के मुख्य नष्कर्ष क्या हैं?

- गरीबी दर में कमी:
  - ग्रामीण गरीबी: यह वर्ष 2011-12 के 25.7% से घटकर वत्ति वर्ष 24 में 4.86% रह गई।
  - शहरी गरीबी: यह वत्ति वर्ष 2024 में लगभग 4.09% (जो 2011-12 में 13.7% थी) थी।

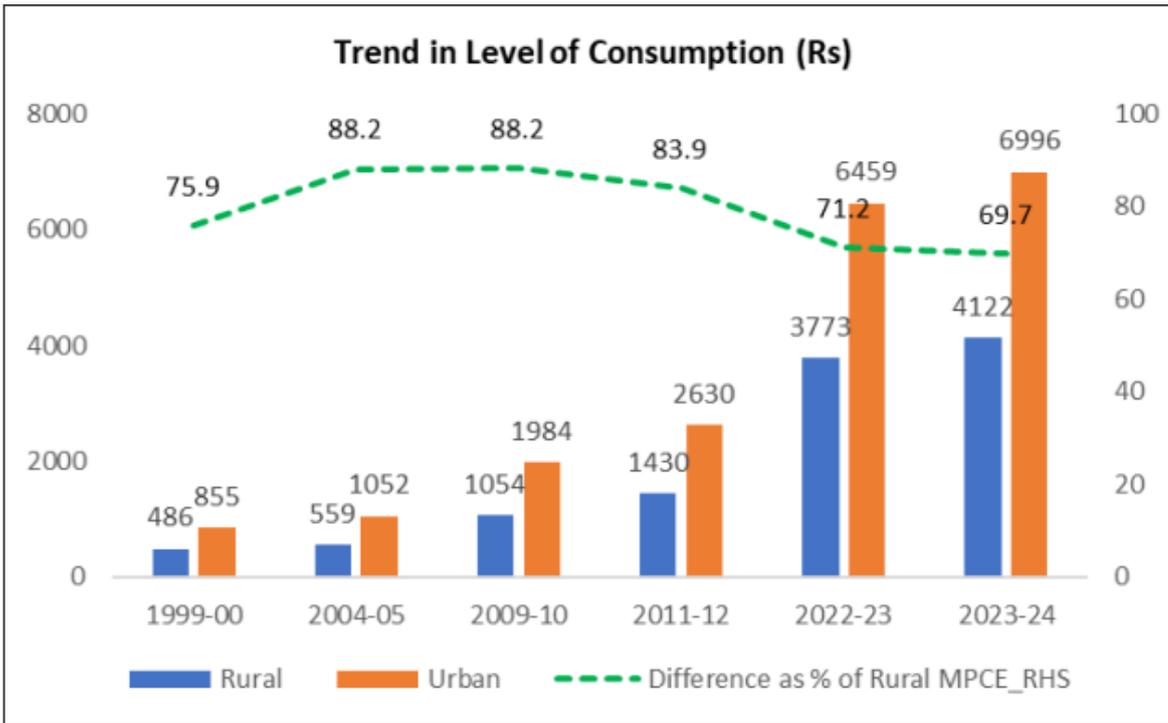
Estimates of Poverty Ratio using Household Consumption Expenditure Survey



- सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), बुनियादी ढाँचे के विकास तथा किसान-केंद्रित पहलों से ग्रामीण आजीविका में सुधार होने के साथ उपभोग असमानता में कमी आई है।
  - आय सहायता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित लक्ष्मि कार्यक्रमों से कम आय वर्ग के लोगों को काफी लाभ पहुँचा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर उपभोग: ग्रामीण उपभोग में तीव्र वृद्धि हो रही है और यह शहरी उपभोग के बराबर पहुँच रही है। ग्रामीण मासिक प्रति

व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) यानी शहरी और ग्रामीण खपत के बीच का अंतर (जैसे ग्रामीण खपत के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है) कम हो रहा है।

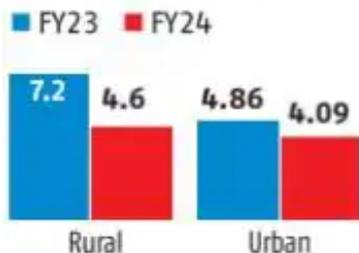
- यह वर्ष 2004-05 के 88.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 69.7% हो गया जो ग्रामीण एवं शहरी खर्च के बीच कम होते अंतर को दर्शाता है।



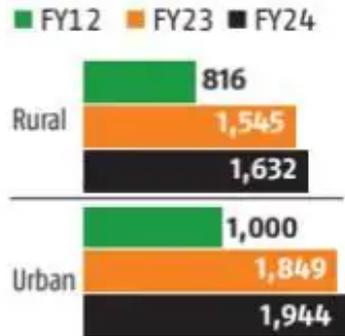
- नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (अगस्त 2023-जुलाई 2024) के आँकड़ों से भी इसकी पुष्टि हुई है जिसमें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच MPCE में अंतर में कमी आने का संकेत दिया गया है, जो वर्ष 2011-12 के 84% से घटकर वर्ष 2022-23 में 71% तथा 2023-24 में 70% हो गया।
- गरीबी रेखा की परिभाषा: मुद्रास्फीति और आरोपण कारकों के समायोजन के बाद वित्त वर्ष 24 में अनुमानित गरीबी रेखा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 1,632 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 1,944 रुपए है।
  - इससे पहले वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गरीबी की सीमा 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिये 1,000 रुपए निर्धारित की थी।

## DROP IN DEPRIVATION

Poverty ratio using household consumption survey (in %)



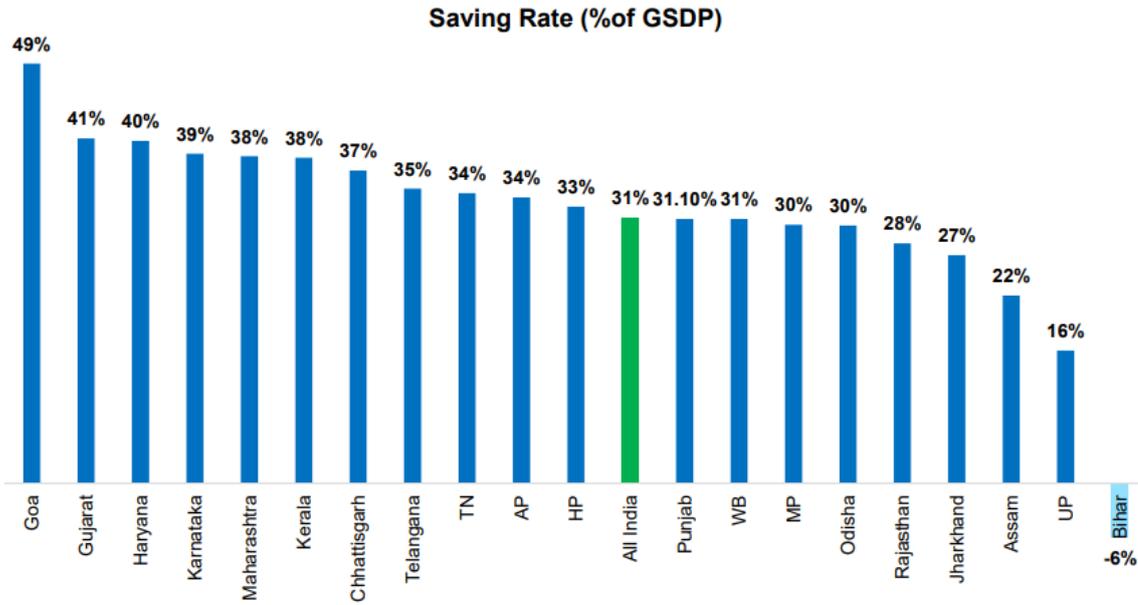
Inflation adjusted poverty line (in ₹)



Source: SBI Report

- राज्यवार बचत: राज्यवार बचत दर का अनुमान MPCE और प्रतिव्यक्ति आय का उपयोग करके लगाया गया, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या वितरण को शामिल किया गया।
- उच्च आय वाले राज्यों की बचत दर, राष्ट्रीय औसत 31% से अधिक है, जो मज़बूत वित्तीय स्थिरता का संकेत है।
- उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कम आय वाले राज्यों में बचत दर कम है, जिसका कारण संभवतः उच्च बाह्य प्रवास है जिससे आय एवं उपभोग पैटर्न प्रभावित होता है।
  - बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी बचत दर नकारात्मक -6% है।

- उच्चतम (गोवा: 49%) और न्यूनतम (बिहार: -6%) बचत दरों के बीच महत्वपूर्ण असमानता है।



#### ■ मुद्रास्फीति का प्रभाव:

##### ○ उपभोग मांग की लोच:

- उपभोग मांग लोचदार है ( $|e| > 1$ ), जिसका अर्थ है कि खाद्य कीमतों में परिवर्तन खाद्य व्यय सहित समग्र व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण MPCE में कमी आती है, तथा न्यून और उच्च आय वाले दोनों राज्यों में नकारात्मक लोच यह दर्शाती है कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, मांग के न्यून के अनुरूप, उपभोग को कम करती है।
  - न्यून आय वाले राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र बढ़ती खाद्य कीमतों से अधिक प्रभावित हैं, जो उनकी अधिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।
- इसके विपरीत, कम खाद्य मुद्रास्फीति मध्यम आय वाले राज्यों में MPCE को बढ़ाती है, जहाँ सकारात्मक लोच यह दर्शाती है कि कम खाद्य मुद्रास्फीति से उपभोग बढ़ता है और मांग बनी रहती है।
  - मध्यम आय वाले राज्यों के शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ MPCE में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

#### ■ क्षेत्रीय असमानताएँ:

- ग्रामीण-शहरी अंतर का प्रभाव न्यून आय वाले राज्यों में कम है, लेकिन उच्च आय वाले राज्यों में यह अधिक स्पष्ट है।
- इससे पता चलता है कि न्यून आय वाले राज्यों के ग्रामीण लोग उच्च आय वाले राज्यों की तुलना में जोखिम लेने के प्रति अधिक सतर्क हैं।

## गरीबी उन्मूलन के लिये सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री सट्रीट वेंडरस आत्मनिर्भर नधि-PM स्वनिधि
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
- राष्ट्रीय पोषण मशिन (NNM)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. नरिपेक्ष तथा प्रतिव्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018)

- औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
- कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
- नरिधनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है।
- नरियात की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ता है।

उत्तर: (c)

प्रश्न. कसिी दयिे गए वरुष में भारत के कुऑ राजुऑों में आधुकरिकि गरीबी रेखाएँ अनुय राजुऑों की तुलना में उऑऑतर हैं कुऑऑकि: (2019)

- (a) गरीबी की दर अलग-अलग राजुऑों में अलग-अलग होती है ।
- (b) कीमत- स्तर अलग-अलग राजुऑों में अलग-अलग होता है ।
- (c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राजुऑों में अलग-अलग होता है ।
- (d) सारवजनकि वतिरण की गुणवत्ता अलग-अलग राजुऑों में अलग-अलग होती है ।

उत्तर: (b)

प्रश्न. UNDP के समरुधन से 'ऑऑऑऑऑऑ ऑऑऑऑऑऑ एवं मानव वकिस नेतृत्व' द्वारा वकिसति 'बहुआयामी नरिधनता सूऑऑऑऑ' में नमिनलखिति में से ऑऑऑ-सा/से सम्मलिति है/हैं? (2012)

- 1. पारवारिकि स्तर पर शकुषा, सुवासुथुय, संपतुत और सेवाओं से वंऑन
- 2. राष्ट्रीय स्तर पर करुय शकुत समता
- 3. राष्ट्रीय स्तर पर बऑऑ ऑऑऑ की मातुता और GDP की वकिस दर

नमिनलखिति कुऑऑों के आधार पर सही उत्तर ऑुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/all-reports-on-decline-in-poverty-in-india>

